मान्यता वापस की गई थी फिर उनकी मान्यता रिस्टोर की गई। जो असेस्मेंट बोर्ड था उसकी तरफ से एक साल तक रोक कर फिर मान्यता वापिस की गई। इसलिए 1981 के बाद फिर उनके परीक्षा लेने का अधिकार मिला हुआ है और वह चल रहा है। हमारे पास जैसे ही शिकायत आई, उस पर हमने काम शुरू किया और आगे भी यदि कोई तथ्य हमारे सामने लाए जाएंगे तो हमारी ओर से निश्चित रूप से पूरी तरह से जांच की जाएगी।

Funds to States under National Agriculture Insurance Scheme

*363. SHRI GANDHI AZAD: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the State Governments are implementing New agriculture Policy-2000; and

(b) if so, how many States have availed of funds on account of National Agriculture Insurance Scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The first ever National Agriculture Policy was announed in July, 2000. Various Central Sector and Centrally Sponsored Schemes are being implemented by the Government of India and the State Governments for development of agriculture and allied activities as envisaged in the Agriculture Policy. Several major initiatives have been taken in the recent past to accelerate the pace of development and implement the objectives of the National Agriculture Policy, such as introduction of the Macro Management Scheme, preparation of common guidelines for Watershed Development Programmes, creation of Watershed Development Fund with a corpus of Rs. 200 crore, launching of a Technology Mission for the Integrated Development of Horticulture in North Eastern States, introduction of a Scheme for seed crop insurance, establishment of a Seed Bank, measures for increasing the availability of farm credit, introduction of a subsidy linked credit scheme for construction/modernization and expansion of cold storages and storages for horticulture produce, expansion of the corpus of the Rural Infrastructure Development Fund, launching of a Market Information Network and promotion of value addition in agriculture through excise exemption and other interventions.

(b) National Agriculture Insurance Scheme (NAIS) or 'Rashtriya Krishi Bima Yojna' was introduced from 1999-2000 Rabi season by the Government of India with a view to enlarging coverage in terms of farmers, crops and risks. Under the scheme, funds are released to the Implementing Agency, *i.e.* General Insurance Corporation of India, who settle the indemnity claims based on the yield data received from the State/UT Governments. These claims are shared between the Central Government and State Government on 50:50 basis. At present, the scheme is being implemented by 18 States and 2 Union Territories.

श्री गांधी आज़ाद: सभापति महोदय, मंत्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया है, उसको देख कर मुझे पूर्व की एक कहावत याद आ रही है जिसमें यह कहा गया है उड़द का भाव पूछे बनऊर छः पसेरी। पूछा क्या जा रहा है और मंत्री जी द्वारा उत्तर क्या दिया जा रहा है, दोनों में विरोधाभास है। प्रश्न (क) के उत्तर में बताया गया है कि पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जुलाई, 2000 में की गई और हाल ही में विकास की गति तेज करने और राष्ट्रीय कृषि नीति के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न मुख्य मुद्दे उठाये गये हैं। मंत्री जी द्वारा उसमें कई स्कीमें निगाई गई हैं कि विकास के लिए यह किया गया है। लेकिन पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो जब से यह कृषि नीति की घोषणा की गई है जुलाई से सितम्बर, 1998 के तिमाही आंकड़ों को देखा जाए तो तिमाही के विकास की गति जुलाई से सितम्बर, 1998 तक 4.9 थी। जुलाई से सितम्बर 1999 में यह गति 1.2 हो गयी। जुलाई से सितम्बर, 2000 तक यह गति लगातार घटकर 0.5 हो गयी। वार्षिक गति को देखा जाए तो 3 वर्षों के रिकार्ड के अनुसार-1998-99 में यह गति 7.1 थी, 1999-2000 में 0.7 रही, 2000-2001 में 0.2 रही। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या विकास की गति को तेज करने के लिए यह नीति निर्धारित की गयी या विकास की गति को गिराने के लिए यह बनायी गयी है? पहली राष्ट्रीय नीति की जब से घोषणा की गयी है, कृषि के विकास की तिमाही और वार्षिक गति में क्या प्रगति हुई है और सरकार इस विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश-वार कितना धन व्यय कर रही है?

श्री श्रीपद यस्सोनाईक: महोदय, माननीय सांसद ने कुछ प्रश्न उठाए हैं। हमारी कृषि नीति जो है वह सन् 2000 से शुरू हुई है और जिस कृषि नीति का हमने जिक्र किया है इस कृषि नीति का इंप्लीमेंटेशन अब शुरू हुआ है। यह इंप्लीमेंटेशन जैसा हमने सोचा है इसको पूरा करने में कम से कम 20 साल तो लगेंगे। कृषि नीति बनाने में ही कम से कम अभी तक 10 साल हो गए हैं। 10 साल के बाद यह कृषि नीति आई है। तो माननीय सदस्य से मैं विनती करता हूं कि कम से कम थोड़ा रुकें। इसका इंप्लीमेंटेशन अभी शुरू हुआ है। जल्दी ही उसके कुछ नतीजे आ जाएंगे। इसमें थोड़ा वेक्त लगेगा।

श्री गांधी आज़ाद: मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न है। महोदय, हमने सीधा-सीधा प्रश्न किया था कि क्या राज्य सरकारें कृषि नीति, 2000 को लागू कर रही हैं? यदि हां, तो कितने राज्यों को राष्ट्रीय

कृषि बीमा योजना के लिए निधियां प्राप्त हुई हैं? ''ख'' में मान्यवर मंत्री जी का जवाब आया है कि भारत सरकार द्वारा रबी, 1999-2000 मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गयी है जिसका उद्देश्य किसानों, फसलों और जोखिमों में लाभ देने के लिए है और 50-50 परसेंट राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की भागीदारी है। इस प्रकार 18 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अभी तक क्रियान्वित किया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रबी, 1999-2000 और खरीफ 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के द्वारा राज्यवार कितने किसानों को लाभ पहुंचाया गया है और राज्यवार केन्द्र सरकार द्वारा इस मद में कितना धन खर्च किया गया है?

श्री श्रीपद यस्सोनाईक: सभापति जी, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस पालिसी भी सन् 2000 से शुरू हुई है और इससे पहले एक कंप्रीहेंसिव क्राप इंश्योरेंश पालिसी थी और इसके बाद में (**व्यवधान**) आ रहा हूं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है-रबी, 1999-2000 तक कितने फारमर्स कवर हुए—उसके मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं। रबी, 1999--2000 तक 5.74 लाख फारमर्स इसमें कवर हुए। खरीफ, 2000 में 85.69 लाख फारमर्स कवर हुए। इसमें एरिया कवर हुआ-7.80 लाख हेक्टेयर्स, खरीफ-2000 में 132.31 लाख हेक्टेयर कवर हुआ। जो सम इंश्योर्ड हुआ है सर, वह है 339.12 करोड़ रुपए 1999-2000 रबी में और खरीफ 2000 में 6918 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस हुआ है। इंश्योरेंस चार्जेज जो हैं सर, 1999 रबी के, यें हैं—5.25 करोड़ रुपए, वैसे ही खरीफ 2000 के 204.35 करोड़ रुपए।

श्री गांधी आज़ाद: महोदय, राज्यवार तो कोई जवाब आया नहीं।...(**व्यवधान**)

श्रीमती गुरचरण कौर: माननीय सभापति जी, पंजाब प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का पंजाब को अब तक कितना लाभ हुआ है और सभी किसानों को कब तक लाभ हो जाएगा?

श्री श्रीपद यस्सोनाईक: सभापति महोदय, पंजाब ने अभी तक नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम में भाग नहीं लिया है। इसका कारण यह है कि उनकी जो पैडी और व्हीट की फसल है वह कम रिस्क वाली है। अब तक हम जो प्रीमियम रखते हैं वह 1.5 या 2 परसेंट है। यह इन्टरेस्ट में ऐड हो जाता है। इस कारण वे उसमें भाग नहीं ले रहे हैं। इसलिए मैं उसका ब्यौरा नहीं दे सकता।

SHRI S.B. CHAVAN: Mr. Chairman, Sir, I would like to have clarifications from the hon. Minister on two or three issues. The first is that the other day I raised the issue of a new kind of a cottonseed which is Boll-worm-resistant. ..(*Interruptions*)... I do not know what the problem is. ..(*Interruptions*)... If the hon. Minister has any problem, I can put some other question. ..(*Interruptions*)... But this question is definitely covered under the Agriculture Policy that the hon. Minister has made. The other day I had raised this issue that in the cotton

growing areas a new kind of a cottonseed has been found out, and which, in fact, has been found to be Boll-worm-resistant. This is the main thing because of which a large number of areas are being affected in the cotton growing areas. But to my great surprise, I was given to understand that in spite of all that, there is a resistance on the part of the ICAR which comes under the Ministry of Agriculture. That is why I am requesting the hon. Minister to kindly let us know what exactly are the reasons for this because when this seed is so good and when thousands and lakhs of agriculturists are going to be benefited, why is it being resisted by the ICAR? In Andhra Pradesh, if I am not mistaken, a huge area was affected. There is a regular lobby of manufacturers of spurious drugs who are distributing these spurious drugs throughout the country. They are resisting this kind of a new variety of seed because if this new seed comes, then their business will be totally affected. Therefore, this lobby is opposing this. I would like to know the reasons for the same from the hon. Minister. This is number one. Another point is that because of population explosion, the areas where there is a scarcity of water, we have to think in terms of using new methods of using irrigation water, what we call the drip irrigation. If we adopt drip irrigation, the area covered will almost be three or four times more. Now, there is a scheme under which subsidy is being provided by the Government of India. I would like to understand whether the Government is seriously considering in the interest of having a greater area covered by irrigation, some incentive subsidy. This subsidy needs to be increased. That is another thing on which I would like to have information from the hon. Minister. The third point is very important. ..(*Interruptions*)... This is a very important issue which I am raising. If the hon. Minister has information, he should kindly respond to my questions. ..(*Interruptions*)... Sir, in the name of tourism large areas of land of the tribal people and poor people are being taken over by interested parties. I am given to understand that taking over of these areas goes totally against the Land Ceiling Act. But, a provision in that Act says that it automatically becomes non-agriculture. So, the question of asking anybody does not arise. I would like to know from the hon. Minister as to how many States are there where such issues have totally been misused by those who are talking in terms of having tourist interest. How many States are there where such a thing has happened? I would like to bring to the notice of the hon. Agricultural Minister that when the State Government enacts any legislation, it requires the concurrence of the Government of India. Will the hon. Minister kindly go through it and, if it is not readily available, kindly make it available to me and let me know as to how many States are there where such a thing has taken place? A huge mass of land

belonging to tribal and other small people has been taken over by the respective parties with the assistance of the State Government concerned.

MR. CHAIRMAN: The Minister may reply to his supplementaries. But, none of the supplementaries arises out of the main question.

SHRI S.B. CHAVAN: Sir, it is relating to the Agricultural Policy...

MR. CHAIRMAN: No, no. The question is relating to the National Agriculture Insurance Scheme.

SHRI S.B. CHAVAN: No, no. If you look at part (b) of the question, it says that how many States have availed of...

MR. CHAIRMAN: Second part is related to first part. That is why all questions are on Agricultural Insurance...

SHRI S.B. CHAVAN: This is totally relating to Agricultural Policy.

MR. CHAIRMAN: Anyway, if the Minister wants to reply, he can do so.

श्री श्रीपद यस्सोनाईक: सर, माननीय सदस्य ने जो दो प्रश्न पूछे हैं मैं उन के बारे में थोड़ा सा विवरण देना चाहता हूं। सर, माननीय सदस्य ने जो बी.टी. कॉटन वाला मामला उठाया, मुझे उस के बारे में कहना है कि इस की अभी ट्राइल चल रही है और हम ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के पास इनफॉर्मेशन भेजी है। उन की क्लिअरेंस आने के बाद ही इस बारे में विचार किया जाएगा। दूसरे, माननीय सदस्य ने ड्रिप इरिगेशन के बारे में पूछा है। मैं बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर पॉलिसी में हम ने मैक्रो मैनेजमेंट की स्कीम बनाई है और यह सब कुछ उस के अंतर्गत आता है। उस में स्टेट गवर्नमेंट को पूरी आजादी है और वह उसमें जितना चाहे पैसा लगा सकती है। सर, माननीय सदस्य के तीसरे प्रश्न के बारे में अभी इनफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मैं माननीय सदस्य को वह इनफॉर्मेशन बाद में भेज दूंगा।

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के भाग 'ख' के संदर्भ में बताया है कि केवल 18 राज्य और दो केन्द्र शासित राज्यों में इस योजना को लागू किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे शेष राज्य कौन से हैं जिन में यह बीमा स्कीम लागू नहीं हो पाई है और उस के कारण क्या हैं? श्रीमन्, मेर प्रश्न का 'बी' पार्ट यह है कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया यह बीमा योजना लागू हो गयी है। कृषकों को उस की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए प्रेरित करने को किस एजेंसी को नामित किया गया है।

श्री श्रीपद यस्सोनाईक: महोदय, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 18 राज्यों और दो यूनियन टेरिटरीज में लागू की गयी है। इन के नाम मैं पढ़ देता हूं और जो इस सूची में नहीं हैं, उन को

आप इस में से निकाल सकते हैं। ये हैं: आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल व सिक्किम और दो यूनियन टेरिटरीज अण्डमान निकोबार और पांडिचेरी हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री रमा शंकर कौशिक: किसानों को उस की औपचारिकता पूरी करने की प्रेरणा देने के लिए आप ने किसी एजेंसी को नामित किया है? काश्तकारों को कौन बताएगा कि अगर बीमा का लाभ उठाना है तो तुम्हें यह करना है?

श्री श्रीपद यस्सोनाईक: सर, जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, इसका पूरा विवरण हमने राज्य सरकारों को दिया है और एग्रीकल्चर इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है।

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन, यह तो भारत सरकार की योजना है, बीमा योजना भारत सरकार की योजना है।

श्री श्रीपद यस्सोनाईक: हर स्टेट में, इस बारे में यदि किसी को कोई इन्फारमेशन चाहिए, वे राज्य सरकार से ले सकते हैं।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, the National Agriculture Policy, announced in July, 2000 by the then Agriculture Minister, Shri Nitish Kumar, who is also sitting here, has also not been able to address the problems faced by the coconut farmers. The policy very specifically states: "For the integrated development of horticulture in North-Eastern States, a Technology Mission will be launched." That means there is a proposal to have a Technology Mission, as far as coconut integrated development is concerned. The coconut farmers are facing severe problems, both in cultivation and in coconut marketing. Even the minimum support price declared this year is very low as compared to that of the last year. Considering all these aspects, I would like to know from the hon. Minister, whether a National Coconut Technology Mission will be launched, as a part of the new Agricultural Policy? Secondly, I would also like to know whether the proposals pending for a long time will be implemented.

श्री श्रीपद यस्सोनाईक: सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उसके बारे में मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा जो नेशनल कोकोनट बोर्ड है और इसकी तरफ से कोकोनट डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है, वह सही है और केन्द्र सरकार ने और हमारी मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर, टैक्नोलॉजी मिशन के बारे में, अब तक विचार नहीं किया है। जब कोई विचार हो जाएगा तो हम माननीय सदस्य को बता देंगे।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, in the course of the reply, the Minister has mentioned the reasons for non-introduction of BT cottonseeds in Andhra Pradesh. Cotton is grown abundantly in Andhra Pradesh. The entire House is aware of the miserable conditions in which the cotton-growing farmers are living. We had recommended for the introduction of BT cotton which has been tested in so many countries, including China, Mexico, Australia and the United States. The Minister has said that they will do it only after they get a clearance from the Ministry of Environment. Sir, in this connection, I had led a delegation to the Ministry of Environment. They told us that they are unable to give clearance because the CSIR people have opposed it. The Minister is giving incorrect information. Can the Minister assure that by this November the farmers will be allowed to use the BT cottonseeds? Sir, the BT cottonseeds have got very positive features. It has the best resistance; its yield is high; its quality is good; and the farmers will have to incur less cost of production.

श्री श्रीपद यस्सोनाईक: सर, बी.टी. कॉटन के बारे में मैंने अभी उत्तर दिया था। हमारा जो आई.सी.आर. है, उसके अंदर उसका ट्रायल चल रहा है और ऐन्वायरनमेंट एंड फारेस्ट मिनिस्ट्री ने उसके बारे में एक कमेटी तय की है, जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी और आई.सी.आर. का ट्रायल पूर्ण नहीं होगा, तब तक यह होना मुश्किल है।

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Sir, a Crop Insurance Scheme was in operation since 1985. One of the major criticisms against that Crop Insurance Scheme was that many crops like cotton, beetle leaves, banana, coconut, arecanut, lichi, mango, are not covered under it. The National Agricultural Policy also states that all the farmers and all the crops will be covered by this insurance scheme. It also states, "An endeavour will be made to provide a package insurance policy for the farmers, right from the stage of sowing of the crop to post-harvest operations, including market fluctuations in the prices of agricultural produces." I would like to know from the hon. Minister whether the present Crop Insurance Scheme covers all the crops or not. I would also like to know from the hon. Minister as to how many of the aspects, stated in the National Agriculture Policy, are covered by the New Agriculture Insurance Scheme that has been announced by the Government.

श्री श्रीपद यस्सोनाईक: सभापति महोदय, कुछ क्रॉप्स नेशनल इंश्योरेंस स्कीम में कवर्ड हैं और कुछ कवर्ड नहीं हैं, इसके बारे में डॉटा कलेक्शन शुरू हो गया है और यह डॉटा कलेक्ट हो जाने के बाद हम फिर इस पर विचार करेंगे।

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Sir, I had asked whether the present Crop Insurance Scheme covers all the crops or not, I also wanted to know how many of the aspects, stated in the National Agriculture Policy, are covered by the New Agriculture Insurance Scheme. The hon. Minister has not replied to my these specific questions.

श्री श्रीपद यस्सोनाईक: जैसा मैंने पहले बताया है ऐग्रीकल्चरल पालिसी के इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, इसके इंप्लीमेंटेशन में कई वर्ष लगेंगे।

MR. CHAIRMAN: He has put a specific question as to which crops are included in the Scheme. You have not replied to that question.

श्री श्रीपद यस्सोनाईक: इस स्कीम के अंतर्गत सभी फूडग्रेन्स को इन्क्लूड किया गया है ...(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Now, next question.

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकार कर लीजिए।

श्री श्रीपद यस्सोनाईक: जो हमारी हार्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, जो ईयरली यील्ड देती हैं, उनको नेशनल इंश्योरेंस स्कीम में शामिल किया गया है। कई पेड़ और झाड़ जैसे काजू, आम, इनकी लाईफ 20-30 वर्ष होती है, इसलिए इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है ...(**व्यवधान**)

श्री मूल चन्द मीणा: महोदय, यह लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है।

श्री सभापति: इस पर हाफ-ऐन-ऑवर डिस्कशन दे देंगे।

Observatory in Laddakh

*364. SHRI B. J. PANDA: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) what is the project cost of the observatory in village Hanel in Laddakh and by when it is going to be completed;

(b) what are the main features of this observatory;

(c) whether there is any scheme to expand the observatory; and

(d) if so, the details thereof, including cost estimates and time schedule for completion of the project?

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.